INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 7 | AUGUST – 2025

"भारतीय समाज में जातीय संघर्ष और चिंतित भारत"

डॉ. साधना आदिवासी
एम.ए., पी–एच.डी. (समाजशास्त्र)
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

भारतीय समाज में जातीय संघर्ष की प्रकृति, कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करता है। भारत में जाति व्यवस्था एक ऐतिहासिक सामाजिक संरचना रही है, जिसने समय के साथ असमानता, भेदभाव और संघर्ष को जन्म दिया। आज भी दलितों और पिछड़ी जातियों को शिक्षा, रोजगार, विवाह और सार्वजनिक जीवन में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आरक्षण नीति, राजनीतिक ध्रुवीकरण, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएँ जातीय तनाव को और गहरा करती हैं। यह संघर्ष न केवल सामाजिक एकता को बाधित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय विकास को भी प्रभावित करता है। शोध पत्र का उद्देश्य इन संघर्षों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आयामों को उजागर करना और उनके समाधान के लिए प्रभावी नीतिगत तथा सामाजिक सुझाव प्रस्तुत करना है। जातीय भेदभाव से मुक्त, समरस और समानतामूलक समाज की स्थापना के लिए जागरूकता, शिक्षा और सशक्तिकरण आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द – भारतीय समाज, जातीय संघर्ष, चिंतित भारत, विश्लेषण अध्ययन।

प्रस्तावना –

भारत एक सांस्कृतिक, भाषायी और सामाजिक विविधताओं वाला देश है, जिसकी पहचान विश्वभर में ''विविधता में एकता'' के रूप में होती है। लेकिन इस विविधता के भीतर एक जटिल और गहराई से जमी हुई सामाजिक संरचना मौजूद है जाति व्यवस्था, जो भारत के सामाजिक ताने–बाने का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यद्यपि भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया है, लेकिन जाति आधारित भेदभाव और संघर्ष आज भी सामाजिक वास्तविकताओं में स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं।

जाति एक सामाजिक पहचान मात्र नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की उपलब्धता और सीमाओं को तय करने वाला एक कारक बन गई है। यह पहचान व्यक्ति के जन्म से जुड़ी होती है, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु यह उसके सामाजिक दर्जे, शिक्षा, विवाह, नौकरी और यहां तक कि सम्मान को भी प्रभावित करती है। भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, जिसकी जड़ें वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था में देखी जाती हैं। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित थी, परंतु कालांतर में यह जन्म आधारित कठोर जातीय श्रेणियों में बदल गई और सामाजिक भेदभाव का आधार बन गई।

ब्रिटिश शासनकाल में जातीय पहचान को और अधिक मजबूत किया गया। अंग्रेजों द्वारा की गई जाति आधारित जनगणनाओं और प्रशासनिक नीतियों ने जातीय वर्गीकरण को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया और समाज

में समानता लाने हेतु अनेक प्रावधान किए। संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 46 में अस्पृश्यता के उन्मूलन, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई। फिर भी, स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी जातीय असमानताएँ बनी हुई हैं। आज भी दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को सामाजिक उपेक्षा, हिंसा, बहिष्कार और आर्थिक व शैक्षिक वंचना का सामना करना पड़ता है। अनेक राज्यों में दलितों को मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है, उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं, और उनके साथ भेदभाव की घटनाएँ सामने आती हैं। ऑनर किलिंग जैसी घटनाएँ, जो प्रेम विवाह में जाति की सीमाओं को पार करने पर होती हैं, इस सामाजिक विघटन को और अधिक गंभीर बनाती हैं।

राजनीतिक स्तर पर भी जाति एक सशक्त और प्रभावी उपकरण बन गई है। जाति आधारित राजनीति, वोट बैंक की रणनीति, और आरक्षण की मांगों ने सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है। सामाजिक संगठनों और आंदोलनों द्वारा जातीय पहचान को केंद्र में रखते हुए किए जाने वाले प्रदर्शन, रैलियाँ और विरोध, समाज में तनाव का कारण बनते हैं।

शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में जातीय संघर्ष के रूप बदल रहे हैं। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार और हिंसा प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, वहीं शहरी समाज में जातीय पूर्वाग्रह शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक मेलजोल में परोक्ष रूप से सामने आते हैं। डिजिटल युग में यह संघर्ष सोशल मीडिया पर भी दिखाई देने लगा है, जहाँ जातीय टिप्पणियाँ और भाषाई हिंसा समाज को विभाजित करने का कार्य कर रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि भारतीय समाज जातीय संघर्ष की इस जटिलता को गंभीरता से समझे और इसका समग्र विश्लेषण किया जाए। यह शोधपत्र इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसमें जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति, प्रभाव और समाधान के मार्गों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। केवल संवैधानिक प्रावधानों या आरक्षण से जातीय समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि मानसिकता में परिवर्तन, सामाजिक संवाद और समावेशी विकास के लिए ठोस प्रयास आवश्यक हैं। जब तक जाति के आधार पर समाज में भेदभाव होता रहेगा, तब तक भारत का लोकतंत्र और सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। इसी विचार के साथ प्रस्तुत यह अध्ययन ''भारतीय समाज में जातीय संघर्ष और चिंतित भारत'' विषय पर एक शोधपरक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

शोध उद्देश्य –

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था केवल एक सामाजिक ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है जो व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में अनेक संवैधानिक प्रयास हुए हैं, किंतु आज भी जातीय भेदभाव और संघर्ष समाज के विभिन्न स्तरों पर देखने को मिलते हैं। इन संघर्षों के कारण केवल ऐतिहासिक नहीं हैं, बल्कि वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और आर्थिक असमानताओं में भी निहित हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि जातीय संघर्ष की गहराई को समझा जाए और इसके विविध पहलुओं का विश्लेषण किया जाए। इसी दिशा में यह शोधपत्र कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है –

(1) भारतीय समाज में जातीय संघर्ष के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों की पहचान करना और उनके प्रभावों का विश्लेषण करना।

(2) वर्तमान समय में जातीय संघर्ष के नए रूपों जैसे– आरक्षण–विरोध, ऑनर किलिंग,राजनीतिक ध्रुवीकरण का अध्ययन करना और उनके सामाजिक परिणामों का मूल्यांकन करना।

शोध विधि –

यह शोध कार्य मुख्यतः वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक स्वरूप का है। इसमें द्वितीयक स्रोतों जैसे शोध–पत्र, पुस्तकें, सरकारी रिपोर्टें, समाचार पत्र, सामाजिक सर्वेक्षण और जनगणना आँकड़ों का अध्ययन किया गया है। इसके माध्यम से जातीय संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान घटनाएँ और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आँकड़ों एवं रिपोर्टों का भी अध्ययन किया गया है, ताकि शोध निष्कर्ष साक्ष्य आधारित और तर्कसंगत बन सकें।

विश्लेषण –

भारतीय समाज में जातीय संघर्ष एक बहुआयामी और जटिल समस्या है, जिसकी जड़ें प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में निहित हैं। यह संघर्ष केवल ऐतिहासिक अन्याय का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र में व्याप्त असमानताओं और भेदभाव से भी उत्पन्न होता है। भारत की जाति व्यवस्था मूलतः वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न हुई, जो आरंभ में कर्म और गुणों पर आधारित थी, लेकिन कालांतर में यह जन्म आधारित बन गई और सामाजिक श्रेणियों के बीच ऊँच–नीच, शुद्धता–अशुद्धता और अवसरों के वितरण में व्यापक भेदभाव पैदा हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि उच्च जातियाँ सत्ता, संसाधनों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर काबिज रहीं, जबकि दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियाँ वंचना, अपमान और शोषण की शिकार होती रहीं। यह सामाजिक असमानता धीरे–धीरे संघर्ष और विद्रोह का कारण बनी।

वर्तमान समय में जातीय संघर्ष अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं, जैसे – मंदिर प्रवेश से रोकना, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव करना, मारपीट, बहिष्कार आदि। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह भेदभाव परोक्ष रूप में कार्य करता है, जैसे – नौकरी में अस्वीकार करना, मकान किराए पर न देना या सामाजिक मेलजोल से परहेज करना। एक गंभीर स्वरूप ऑनर किलिंग का है, जहाँ अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवक–युवतियों की हत्या कर दी जाती है। ऐसी घटनाएँ विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आम हैं। यह सामाजिक असहिष्णुता का चरम रूप है, जो समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है।

आरक्षण नीति के कारण भी जातीय तनाव उभरकर सामने आते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन कई बार इसे ''प्रतिभा विरोधी'' कहकर विरोध किया जाता है। उच्च जातियों के कुछ वर्ग इसे विशेषाधिकार के रूप में देख कर आंदोलन करते हैं, जिससे समाज में टकराव उत्पन्न होता है। यह स्थिति तब और अधिक गंभीर हो जाती है जब राजनीतिक दल जातीय समीकरणों के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इससे सामाजिक विभाजन और गहरा होता है।

डिजिटल युग में जातीय संघर्ष एक नए रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया पर जातीय घृणा फैलाने वाले संदेश, ट्रोलिंग, और अपमानजनक टिप्पणियाँ समाज में वैमनस्य को बढ़ावा देती हैं। यह 'डिजिटल जातिवाद' नई पीढ़ी को भी जातीय भेदभाव के माहौल में ढाल रहा है। इसके साथ ही, कुछ फिल्मों, धारावाहिकों और विज्ञापनों में जातीय स्टीरियोटाइप्स को दर्शाकर मानसिकता को और अधिक प्रभावित किया जाता है।

सामाजिक दृष्टि से जातीय संघर्ष सामाजिक एकता, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को क्षीण करता है। आर्थिक रूप से यह अवसरों की असमानता पैदा करता है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग विकास की मुख्यधारा से कट जाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह संघर्ष लोकतंत्र के लिए खतरा बनता है क्योंकि इससे मतदान जाति आधारित हो जाता है और नीतियाँ भी जातीय ध्रुवीकरण से प्रेरित होने लगती हैं। इन सभी पहलुओं से स्पष्ट होता है कि जातीय संघर्ष केवल अतीत की समस्या नहीं है, बल्कि वर्तमान भारत की सामाजिक संरचना के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसे सुलझाने के लिए सामूहिक चेतना, व्यवहारिक बदलाव और नीति स्तर पर ठोस उपायों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष –

भारतीय समाज में जातीय संघर्ष एक ऐसी जटिल समस्या है जो केवल सामाजिक असमानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास को भी गहराई से प्रभावित करता है। संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की नींव रखी, परंतु व्यवहारिक जीवन में जातीय भेदभाव अब भी व्यापक रूप से मौजूद है। दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित वर्गों को आज भी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। राजनीतिक स्तर पर जाति को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना इस समस्या को और गहरा करता है। सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों पर फैलती जातीय घृणा ने संघर्ष को एक नया रूप दे दिया है। अतः आवश्यकता है कि समाज शिक्षा, जागरूकता और नीति–निर्माण के माध्यम से जातीय भेदभाव को जड़ से समाप्त करने के लिए संगठित प्रयास किया जाय, ताकि एक समतामूलक और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण हो सके।

संदर्भ –

1. अंबेडकर, भीमराव रामजी, जाति का विनाश, प्रकाशन प्रभाग, भारत सरकार, मुंबई, 1936
2. शाह, घनश्याम, भारतीय राजनीति में जाति, ओरिएंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, 2002
3. जाफलोट, क्रिस्टोफ, भारत की मौन क्रांति : उत्तर भारत में निचली जातियों का उदय, हर्स्ट एंड कंपनी, लंदन, 2003
4. भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, भारत सरकार प्रकाशन, नई दिल्ली, 2023–24
5. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अपराध आंकड़े रिपोर्ट, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2023
6. विकासशील समाज अध्ययन केंद्र, लोकनीति सर्वेक्षण रिपोर्ट, सीएसडीएस प्रकाशन, नई दिल्ली, 2022।
7. देशपांडे, सतीश, समकालीन भारतः एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली, 2003
8. गुरु, गोपाल, आधुनिकता की तलाश में दलित, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2009
9. ओमवेट, गेल, दलित और लोकतांत्रिक क्रांति, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1994
10. विविध लेखक, जातीय संघर्ष एवं सामाजिक न्याय से संबंधित समाचार लेख, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, विभिन्न स्थान, 2022–2024।